Shri C. R. Pattabhi Raman: There are five minutes more, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: I have to give some time to Mr. Deo also to reply.

Shri C. R. Pattabhi Raman: I wanted to say something about Paradip Port, Kiruburu iron ore mines, etc.

Mr. Deputy-Speaker: The discussion on planning is coming up later on; four hours have been allotted for this. He may refer to all these points then, which are remaining.

Shri C. R. Pattabhi Raman: I am entirely in your hands. I wanted to end with a quotation. It is just likely that the House would like to know what Prof. John R. Howard, President, Lewis and Clark College, who came here recently has said. He has referred to our progress. This is hardly the time to go into that, but he has also referred to the regional development in India.

So, it is not as if we are not aware of it. We are all the time aware of it. We are all the time collecting data. It is not as if I am seeking to defend the Planning Commission. They are continuously writing to the State Governments, asking for data. It is true that some of them have not replied, but they are gathering the necessary data. That is the position, Sir.

Shri P. K. Deo: Sir, I express my sincere thanks to my hon. friends who have supported this resolution. All the speakers have unaimously supported this resolution and they have highlighted the imbalance and the regional disparity in the development of this country. Even though we have completed a decade of planning, nothing has been done in this regard. As the Minister himself has admitted, it was only on the 4th August, 1962 that a circular has been sent to the various States to define the regions and areas which they consider to be backward. Even though, it is belated, I express my thanks to the Ministry that they have at least taken some steps in this direction. Since the very purpose of bringing this important subject to limelight is served, I think I would better ask the leave of the House to withdraw my resolution.

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put Mr. Koya's amendment to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Does the hon. Member, Mr. Deo, have the leave of the House to withdraw his resolution?

Some Hon. Members: Yes.

The resolution was, by leave, withdrawn.

17.08 hrs.

RESOLUTION RE: NATIONALISATION OF BANKS—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further consideration of the resolution regarding nationalisation of banks. 1 hour and 59 minutes are left. Shrimati Subhadra Joshi may continue her speech.

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal): I want to move that further discussion on this resolution may be....

Mr. Deputy-Speaker: Unless she finishes her speech, he cannot move it.

Shrimati Yashoda Reddy (Kurnool): When she is already in possession of the House, how can he move it?

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Subhadra Joshi may continue her speech.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार आप की इजाजत से मैं ने हाउस में प्रस्ताव पेश किया था कि इस इमरजेंसी के समय में तमाम

रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए । मुझे खुशी है कि में ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा । हालांकि इस प्रस्ताव के महत्व को मैं समझती थी, फिर भी लोगों की दिलचस्पी का में पूरा अन्दाजा उस वक्त नहीं कर सकी थी । मैं नहीं समझती थी कि इस विषय में देश के लोग इतनी दिलचस्पी लेंगे । मेरे इस प्रस्ताव को पेश करने के बाद बहुत से लोग मुझ से मिले, जिन में स्टाफ एक्सचेंज में काम करने वाले, कुछ उन के इम्पारटेंट ओहदेदार, बैंक्स में काम करने वाले, और बड़े बड़े जिननैस मैन थे । उन लोगों ने कहा कि हम अपने मुंह से बहुत सी बातें नहीं कह सकते, लेकिन हम को इस बात की खुशी है कि तुम ने सब लोगों का ध्यान इस ओर खींचा है ।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज हमारे डिप्टी फाइनन्स मिनिस्टर साहब, भगत जी, यहां मौजूद हैं, जोकि बड़े क्रांतिकारी मंत्री हैं । मुझे आशा है कि वह इस पर बहुत अच्छी तरह से गौर करेंगे । मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहती हूं कि इस इमरजेंसी के समय यह प्रस्ताव पेश करने के बहुत से कारण थे । पिछले दिनों से हमारी फाइनन्स मिनिस्ट्री देश में समाजवाद लाने की तरफ क्रांतिकारी कदम उठा रही है । फाइनेन्स मिनिस्टर एक नए किस्म का बजट लाए हैं और गोल्ड कंट्रोल जारी किया है ।

मुझ को ऐसी उम्मीद हुई कि हो सकता है कि ऐसे मौके पर फाइनन्स मिनिस्ट्री इस पर और भी ज्यादा ध्यान दे ।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो सदन के सामने मैं आप को यह बतलाना चाहती हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों होना चाहिए और उस से क्या फायदा इस वक्त हो सकता है ? हमारे प्रधान मंत्री ने और बाकी लोगों ने भी कहा कि जिस वक्त चीन का आक्रमण हमारे देश पर हुआ है और हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं उस वक्त सिर्फ वह फौजी जवान ही हमारे देश की रक्षा नहीं करेंगे जोकि सीमा पर जा कर मातृ-भूमि की रक्षा के लिए शत्रु से लोहा लेंगे और जान लेंगे और अपनी जान देंगे, बल्कि जितने भी अन्य काम करने वाले है चाहे वे किसान हो अथवा मजदूर, देश के किसी भी कोने में वे काम करते हों, वे सब लड़ाई में जब तक हिस्सा नहीं लेंगे और अपना कंट्रीब्यशन नहीं करेंगे तब तक हम उस में कामयाब नहीं हो सकते है । ऐसे मौके पर जरूरत है कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज अच्छे तरीके से डेवलप हों और कृषि को अच्छे तरीके से तरक्की हो । तमाम फील्डस में अच्छे तरीके से तरक्की हो और उस में दिलचस्पी लें । मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बैंकिंग का काम है, बैंकिंग सिर्फ बजात खुद ही एक इंडस्ट्री नहीं है बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज की आजकल जितनी कम्पलीकेटेड मशीनरी है उस में भी बैंकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है । यह एक किस्म से की इंडस्ट्री होनी चाहिए और सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से और बड़े बड़े नये उद्योग स्टार्ट होते हैं या पुराने उद्योग धंधे जिस बैंकिंग पर निर्भर करते हैं उस के राष्ट्रीयकरण की बात सोचनी चाहिए ।

मैं यह भी कहूंगी कि हमारे यहां जो मिक्सेड एकोनामी हम लोगों ने मंजूर की है और हम अहिंसा के रास्ते से चल कर समाजवाद इस देश में लाना चाहते हैं और जो दिन रात उद्योग धंधों को दिक्कतें होती हैं, वह भी राष्ट्रीयकरण करने से दूर हो जायेंगी । आये दिन इस हाउस में रिपोर्ट मांगी जाती है कि इस इंडस्ट्री की रिपोर्ट लाओ और उस इंडस्ट्री की रिपोर्ट लाओ, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करूंगी कि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार कर ले तो बहुत सी खराबियां जो आजकल उद्योग

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

धंधों में रोज ब रोज पकड़ी जाती हैं उन चीजों से हम बच सकते हैं और देश में उद्योग धंधे अच्छी तरह से तरक्की कर सकते हैं ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से जो सब से बड़ा लाभ होगा वह मेरे ख़याल में यह होगा कि कम से कम ३५ करोड़ रुपये का सालाना फ़ायदा सरकार को बैंकों से होगा जोकि इन लोगों को प्राफ़िट होता है । इस के पहले कि मैं और बातें कहूं मैं यह बतलाना चाहती हूं कि यह जो ३५ करोड़ रुपये का प्राफ़िट बैंक्स में हुआ है यह नैट प्राफिट है । टैक्सेज और सब चीजें देने के बाद यह प्राफ़िट हुआ है । इस में वह चीज नहीं है जोकि एक सीक्रेट प्राविज़न होता है उन को रिज़र्व्स रखने के लिए, उस को छोड़ कर इतना प्राफ़िट होता है । दूसरा फ़ायदा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से यह होगा कि आज हमारे वहां दिन रात जो इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि सरकार प्राइस लाइन को मेंटेन करे, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से प्राइस लाइन मेंटेन करने में बहुत मदद मिलेगी । मैं आगे चल कर बतलाऊंगी कि जो कर्जा दिया जाता है उस में प्रोड्यूस करने के लिए कितना कम कर्जा दिया जाता है और कितना रुपया उस में इस चीज के ऊपर लगाया जाता है जिस से कि चीजों की कीमतें बढ़ने का मौका मिले । अगर सरकार प्राइस लाइन मेंटेन कर पायेगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद, तो इतना ही नहीं कि प्राइस लाइन जैसाकि उन की पालिसी है, वह कंट्रोल हो जायगी । बल्कि अब जितनी दिन रात मांग आती है तनख्वाह बढ़ाने की या और दूसरी बातों की, उस में भी बड़ा फर्क होगा । इस तरह से रोज जो तनख्वाहें नहीं बढ़ानी पड़ेंगी उस से भी आगे चल कर हमें आर्थिक लाभ होगा ।

एक अन्य चीज मुझे यह कहनी है अगर सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लेगी तो आज बैंक्स जोकि एग्रीकलचरल प्रोडक्शन में कोई पार्टपले नहीं करते हैं और एग्रीकलचरल प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस होता है और उस की सिक्युरिटी में बहुत पैसा देते हैं मगर बाकी एग्रीकलचरिस्ट्स को यह प्राइवेट बैंक्स कोई सहायता नहीं करते हैं, उन को कोई लोन नहीं देते हैं । अगर राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो उन का भी फ़ायदा होगा और उन को भी दे सकते हैं ।

यहां जो विदेशी बैंक हैं और जिन्होंने यहां एक पैसा भी नहीं लगाया है और एक पैसा भी उन की पूंजी नहीं है वह कितना ही मुनाफ़ा इस देश में अपने डिपाज़िट्स से बनाते हैं, वह मुनाफ़ा भी रुकेगा । विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज में हेर फेर दिन रात करते हैं, कभी ऐसी चीजों की क़ीमतों को कम दिखा कर और कभी चीजों कीं क़ीमतें ज्यादा दिखा कर विदेशी मुद्रा में हेरफेर करते हैं वह भी नहीं कर पायेंगे और वह भी रुक जायगा । बहुत से उद्योग धंधों में जो इतना ब्लैक का पैसा जाता है, जो टैक्स इवेड किया जाता है, अगर वह सरकार के हाथ में आ जायेंगे तो उन की पकड़ ज्यादा आसानी से हो सकेगी और यह टैक्स इवेड भी नहीं कर सकेंगे ।

जैसा मैं ने आप से कहा कि जो विदेशी बैंक हैं उन्हों ने यहां कुछ भी नहीं लगाया है तो भी वह यहां से इतने हियूज प्राफिट्स डिक्लेयर करते हैं जिसका कि आप को अंदाजा भी नहीं हो सकता है । जो चार्टर्ड बैंक हैं उसने अकेले सन् १९६३ में ८० लाख का मुनाफ़ा अपने हिसाब में इस बार दिखाया है । इस के अलावा जो १४ एक्सचेंज बैंक्स हैं जिन्हों ने कि यहां एक पैसे की भी पूंजी नहीं लगाई है उन का मुनाफ़ा सन् १९६१ का २.६७ करोड़ के लगभग है । अब आप अंदाजा लगाइये कि बिना पूंजी लगाये हुए ये लोग इतना प्राफिट बना रहे हैं तो सरकार अगर उन का राष्ट्रीयकरण कर दे तो उस की भी बहुत बचत हो जायेगी ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से एक फ़ायदा यह भी होगा कि इस वक्त जो प्राइवेट बक्स हैं उन पर कोई रोकटोक नहीं है । कभी कभी रिजर्व बैंक वाले उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, रोकटोक करने की कोशिश करते हैं तो कभी एक आध बार कोई अफ़सर भी बिठा देते हैं । वह किस को ऐडवांस देते हैं और क्या करते हैं उस पर कोई काबू किसी का नहीं है । अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो हमारी योजना के मुताबिक जितना खर्च करना चाहते हैं, कितना परसेंट एग्रीकलचर पर लगाना चाहते हैं, कितना इंडस्ट्रीज पर लगाना चाहते हैं और कितना अन्य पर लगाना चाहते हैं, योजना के मुताबिक़ उस में से सरकार कर्ज दे सकेगी और उस योजना का अच्छे तरीक़े से इम्प्लीमैंटेशन हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है ।

एक और फ़ायदा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से यह होगा कि इससे लोगों का भरोसा बैंकों पर ज्यादा से ज्यादा होगा । इस वक्त इतनी ब्रांचेज खुलने के बावजूद भी गांवों में एक तो ब्रांचेज इन प्राइवेट बैंकों की नहीं हैं फिर जब पिछले दिनों में गोल्ड का कंट्रोल भी हमारी सरकार ने कर लिया, कोशिश इस बात की है कि लोग सोने में और ऐसी जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, उन में पैसा न रक्खें और उसे बैंक में डालें तो अगर लोगों का बैंकों पर भरोसा रहा और बैंकों पर भरोसा बढ़ा तो लोगों को पैसा जमा करने की आदत पड़ेगी और इससे भी सरकार का फ़ायदा होगा ।

आगे चल कर उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक, दो मिनट इस बात पर रोशनी डालूंगा कि आज कल भरोसा क्यों कम है और किस तरीक़े से सरकार उनका भरोसा बढ़ा सकती है ?

अब इस के बाद जो खर्चा प्राइवेट बैंक्स पर है उस खर्चे को भी देखा जाय । कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें वे लोग देते हैं और कितना अधिक खर्चा करते हैं ? उस खर्चे के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं । इस वक्त रोज हमारे यहां शिकायत होती है । आज मिक्सड एकोनामी की वजह से जो हमारे यहां बड़े बड़े जितने अच्छे आफिसर्स होते हैं वे रिटायर होने के बाद प्राइवेट इंटरप्राइज में चले जाते हैं, प्रोइवेट उद्यगों धंधों में चले जाते हैं । काफ़ी डिसपैरिटी तनख्वाहों में प्रावेइट सैक्टर और पबलिक सैक्टर के बीच में रहती है । जब प्राइवेट सैक्टर में उन को इतनी लम्बी तनख्वाह मिले तो उनको उधर जाने की लालच तो रहती ही है । मसलन मैं आप को बतलाऊं कि जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है वह तो बेचारा ४००० तनख्वाह लेता है और जो चार्टर्ड बैंक का मैनेजर है अपने दूसरे खर्चों के अलावा १०,००० उसे तनख्वाह मिलती है । जब इतनी डिसपैरिटी प्राइवेट बैंक्स और दूसरे बैंक्स में रहती है तो अगर सरकार बैंकों का नेशनलाइज़ेशन कर दे और उन को अपने हाथ में ले ले तो सरकार इस डिसपैरिटी और फर्क को बहुत कम कर सकेगी और आज जो बेचारे डिपाजिटर्स का पैसा लेकर इतने खर्चे किये जाते हैं उन खर्चों को भी कम कर सकेगी ।

अब मैं प्राइवेट बैंक्स के कारोबार के बारे में आप को कुछ बताऊंगा । आप इस को सुन कर आश्चर्य करेंगे कि किस तरह से वे पैसा लगाते हैं और इतनी भारी रकमें जो इस देश के दूसरे अच्छे कामों में लगनी चाहिये, जिन का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, वे कहां खर्च की जाती हैं । कौन लोग हैं जिन्होंने इन बैंक्स पर कब्जा करके रखा हुआ है । हमारे देश में तकरीबन ३०४ बैंक्स हैं । उन में से ८२ शैड्यूल्ड बैंक्स हैं । उन शैड्यूल्ड बैंक्स में से चौदह विदेशी मुद्रा के बैंक हैं जिन की पूंजी यहां पर कोई नहीं लगती है । बाकी के जो बैंक्स हैं, शैड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनके वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ बातें मैं आप के सामने रखना चाहती हूं । इन ६८ बैंक्स में से जिन में विदेशी मुद्रा बैंक शामिल नहीं हैं, ११ बैंक ऐसे हैं जिनका वर्किंग कैपिटल २५ करोड़ से

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

ऊपर है । १३ बैंक ऐसे हैं जिन का बैंकिंग कैपिटल साढ़े सात करोड़ से पच्चीस करोड़ तक है और बाकी जो बैंक हैं, उनका बकिंग कैपिटल साढ़े सात करोड़ से भी नीचे है । सब जो बड़े बैंक हैं उन की पूंजी कितनी है और उनके डिपाजिट्स कितने हैं, इस को आप देखें । सब से बड़े बैंकों की तादाद इस देश में १२ समझी जाती है । उनकी पूंजी सिर्फ १७.९७ करोड़ है और उन के पास डिपाजिट रहते हैं ९६९ करोड़ के करीब । बाकी जो २६९ बैंक हैं, उनकी पूंजी सिर्फ ११.३१ करोड़ है और उन के पास डिपाजिट १९१ करोड़ के करीब रहते हैं । फारेन एक्सचेंज वाले जो बैंक हैं, जो यहां पर कोई कैपिटल नहीं लगाते हैं, उन के पास २५३ करोड़ के करीब डिपाजिट रहते हैं । जो हमारा स्टेट बैंक है उस में १०.५८ करोड़ के करीब पूंजी है और ६६१ करोड़ के करीब उसके पास डिपाजिट हैं । अगर इनका आप औसत लगा कर देखें तो आप को पता चलेगा कि २६ बैंक सिर्फ यानी ८.६ परसेंट बैंक हमारे यहां के ८५ परसेंट डिपाजिट्स को कट्रोल करते हैं । यह स्थिति किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो हो सकती है । कितनी भारी रकमें इतने कम बैंक डिपाजिट्स की शक्ल में अपने पास रखते हैं, इस को आप देखें । कर्जा किन को वे देते हैं, इस को सुन कर आप आश्चर्य करेंगे। अगर प्लान के मुताबिक, योजना के मुताबिक वे कर्जा दें तो मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस बात से एग्री करेंगे कि इस किस्म का उनका नक्शा नहीं बन सकता था जैसा कि आज हमारे सामने है ।

उनके पास १४२० करोड़ के करीब डिपाजिट्स हैं । इस १४२० करोड़ में से जो कर्जा उन्होंने दिया है, उस को मैं आप को बतलाता हूं । ९५.८८ करोड़ तो उन्होंने खाद्य सामग्री के अगेन्स्ट दिया है । ३६७.६२ करोड़ स्टाक एक्सचेंज और बुलियन के अगेन्स्ट दिया हुआ है । ३११.९९ करोड़ जो बना हुआ सामान होता है, जो कंज्यूमर्ज गुड्ज होते हैं, जो फिनिश्ड गुड्ज होते हैं, उनके अगेन्स्ट दिया हुआ है । २२७.८४ करोड़ रुपया उन्होंने इंडस्ट्री में जो मशीनें वगैरह होती हैं, उन के अगेन्स्ट दिया हुआ है । आप देखेंगे कि एग्रिकल्चर को तरक्की के लिए उन्होंने कोई पैसा मेरी इत्तिला के मुताबिक नहीं दिया हुआ है । एग्रीकल्चर की हर रोज इस सदन में चर्चा होती है, प्लानिंग कमिशन के सामने और इस हाउस के सामने हर रोज शिकायत होती है, लेकिन उधर इन बैंक्स का कोई ध्यान हो नहीं गया है ।

अब मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद और फरोख्त में किस प्रकार से बेईमानी होती है, कितना कम रुपया लगाया जाता है । इन सिक्योरिटीज में इनकी वैसे भी दिलचस्पी बहुत कम है । जो ६१८ करोड़ रुपया सरकारी सिक्योरिटीज में लगा हुआ है, उसमें से ज्यादा तर जो है, २६७ करोड़ वह स्टेट बैंक का या उसकी जो सबसिडियरीज हैं, उन का लगा हुआ है । बाकी के तमाम २९६ बैंक्स ने ३६१ करोड़ रुपया ही सरकारी सिक्योरिटीज में लगा रखा है । २५ परसेंट जो इनके एड-वांसिस हैं वे सिर्फ स्टाक एक्सचेंजिज में इन्होंने लगा रखे हैं । इससे आप अंदाजा लगायें कि इनकी देश की तरक्की करने में कहां तक दिलचस्पी हो सकती है ।

ऐसा क्यों होता है, इस को आप देखें । इस से पहले कि मैं इसका जिक्र करूं, मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि १९६१ में रिजर्व बैंक के जो एक्स-गवर्नर हैं, उन्होंने इन बैंक्स के बारे में क्या कहा था । उससे काफी अच्छा प्रकाश इन बैंक्स के बर्किंग पर पड़ता है । उन्होंने कहा था :—

"One of the structural features of Indian banking is the concentration of power which in some cases

is enormous in relation to capital employed. From time to time we come across cases in which a family or a group has got full controlling interest in a bank."

इसका मतलब यह होता है कि बहुत कम लोग हैं जो इन बैंक्स के डायरेक्टर्ज हैं, जिन्होंने इन बैंक्स पर कब्जा कर रखा है, या जिन की मिलकियत ये बैंक होते हैं । छोटे छोटे जो शेयरहोल्डर होते हैं, उन को इनके इंतजाम में कोई दिलचस्पी नहीं रह सकती है और वे घूम फिर कर थोड़े से लोगों के हाथों में आ जाते हैं । हमारे यहां जितने बड़े बड़े बैंक हैं, जैसा कि एक्स-गवर्नर ने बताया है, वे बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में हैं । मिसाल के तौर पर मैं आप को बतलाना चाहती हूं कि सैंट्रल बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ इंडिया लिमिटेड जो हैं, यह कहा जाता है कि टाटा, खटाऊ और मुफ्त लाल ग्रुप के इनफ्लुएंस में ये हैं । ज्यादा तर यह जो ग्रुप है, वही इनको रन करता है . . . .

एक माननीय सदस्य : मफत लाल है मुफ्त लाल नहीं है ।

Shri Heda (Nizamabad): Meaning is the same.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इसी तरह से पंजाब नैशनल बैंक जो है, वह डालमिया जैन ग्रुप के हाथ में है । मैं किसी बैंक विशेष के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूं क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जो लोग पैसा जमा कराते हैं, उन में पैनिक फैले या डर फैले और जैसा थोड़े दिन पहले रश इन बैंक्स पर हो गया था, उसी तरह का रश फिर हो । हमारी बहुत सी संस्थाओं के पैसे पंजाब नैशनल बैंक में रखे हुए हैं । फिर भी मैं इतना कहना चाहती हूं इनकी कुछ कनसर्न के बारे में कि इतनी तहकीकात हो गई, इतने सीरियस चार्जिज लग गये और आज फिर से कोई इनक्वायरी बैठी हुई है जोकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हट गई है, मगर मैं उनकी सेवा में अर्ज करना चाहती हूं कि सीरियस शिकायतें लोग इसके बारे में करते हैं, बहुत से आफिसर्स जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं, उन को हटा देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है । ये जो शिकायतें हैं, इन का मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूं । उन शिकायतों के फलस्वरूप कोई रहे या न रहे, लेकिन उन शिकायतों की जांच तक न हो, यह कहां तक ठीक है इसको आप सोचें । इनकी जांच न करना डिपाजिटर्ज के साथ बड़ा अन्याय करना है । मैं नहीं कहना चाहती हूं कि वे कौन कौन सी शिकायतें हैं । पर मुझे मालूम हुआ है कुछ लोगों से, जैसा उन का कहना है कि करोड़ों रुपया उस ग्रुप ने निकाल करके अपने लिये इस्तेमाल किया हुआ है । उनका कहना है कि बहुत सी गवनमैंट सिक्योरिटीज की खरीद और फरोख्त में बहुत सा रुपया बनाया गया है जिस में सरकार को बहुत नुक्सान हुआ है । जब इतने सीरियस चार्जिज हों, तो कुछ न कुछ तो उस बैंक के बारे में किया ही जाना चाहिये । मैं जानती हूं कि सरकार का जो कंट्रोल है, उसकी वजह से कोई ऐसे बैंक के साथ हादसा नहीं हो सकता है और सरकार उस को बचायेगी । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ लोग तो दिन रात पैसा बनायें और सरकार के कान पर जूं तक न रेंगे और इनक्वायरी तक न हो । चाहे कोई रहे या न रहे, लेकिन इनक्वायरी अच्छी तरह से होनी चाहिये । जिस तरह से दूसरी चीजों को आप ने टेक ओवर किया है, मेरा खयाल है, उसी तरह से इन सब चीजों को देखते हुए पंजाब नैशनल बैंक को सरकार अपने कब्जे में कर ले, उस को टेक ओवर कर ले और इस का बहुत अच्छा केस आप के सामने है ।

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): I am sorry to interrupt the hon. lady Member. I want just a word to say. The

[Shri B. R. Bhagat]

hon. Member herself had said that she did not want to say anything that may injure the creditworthiness of a credit institution like a bank. But, I think, by saying that crores of rupees had been taken out and that these are the allegations and the Government is not doing anything in the matter, she is likely to do the same damage which she wants to avoid. I can assure her and the House that the Reserve Bank has been, not with respect to the Punjab National Bank alone but to any Bank, very particularly interested in seeing that the affairs and the management of banks should be run on very sound lines. And so far as the Punjab National Bank is concerned, it is a very sound bank and there should not be any misapprehension because crores of rupees had been taken out. I want to allay any misapprehension that may be there.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अगर मुझे इस बात का इत्मीनान न होता कि रिजर्व बैंक लोगों के इंटिरेस्ट्स को वाच करेगा, उनकी देखभाल करेगा तो मैं इतनी बात भी आप के सामने न कहती, जितनी मैंने कही है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहती हूं कि अगर कोई एलीगेशंज़ हैं, तो उन की इनक्वायरी हो जानी चाहिये।

Shri B. R. Bhagat: It is being always done.

श्रीमती सुभद्रा जोशी : That is very nice.

इसी तरह से मैं आप को बतला रही थी कि बड़े बड़े बैंक किस तरह से बिज़िनेस वालों के हाथ में हैं।

बैंक आफ बड़ोदा—वालचंद हीराचंद ग्रुप के हाथ में है

यूनाइटेड कामर्शल–बिड़ला ग्रेप के हाथ में बैंक है

इसी तरह से छोटे छोटे बैंक हैं :

हिन्दुस्तान कामर्शल—जे० के० ग्रुप बैंक

हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल—जालान ग्रुप बैंक

कहने का मतलब यह है कि इन बैंकों का इन्तज़ाम आखिर किसी को तो करना ही है। कौन इन्तज़ाम करता है, इस पर किसी को एतराज नहीं है। पर यह बैंक जिन के हाथ में हैं उन के अपने कारखाने हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं और वे अपने धंधे करते हैं। सरकार चाहे कितनी निगरानी करे, उन में से पैसा लेने पर कितने इंटरेस्ट पर वे पैसा लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, या नहीं लेते हैं यह तमाम चीज़ें ऐसी हैं, जिन के लिये मंत्री महोदय ने कहा कि मेरा उन पर इशारा कर देना काफ़ी है, उस से ज्यादा मुझे नहीं कहना चाहिये, पर मैं उन से कहना चाहती हूं कि कई वर्ष पहले जब लाला योधराज पंजाब नैशनल बैंक के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने बयान दिया था। वह कोई सीक्रेट बयान नहीं था। उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि एक ही सिक्योरिटी पर बिना सिक्योरिटी बढ़ाये हुए एक इंडस्ट्री वाला कर्ज़ा लेता है, सिक्योरिटी नहीं बढ़ती है और दूसरे के नाम वह और कर्ज़ा लेता है, फिर तीसरे के नाम से और कर्ज़ा लेता है। यह पंजाब नैशनल बैंक के चेयरमैन का इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने बयान था। अगर उन्होंने उस वक्त यह बयान दिया था तो सरकार को एन्क्वायरी करनी चाहिये कि वह चीज़ें उनके जाने के बाद कंटिन्यू हुई या नहीं, या क्या होता है। इस लिये उन की वर्किंग के बारे में मैं जनरली बतला रही हूं कि यह ख़तरे हो सकते है।

इसके बाद मैं मुनाफ़े के बारे में कहना चाहती हूं। अभी एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि यह मुनाफ़ा कहां से आता है। मुनाफ़ा आता है कम इंटरेस्ट पर लोगों को रुपया डिपाज़िट करने में और ज्यादा इंटरेस्ट पर लोगों को रुपया देने में। इसी तरह से और बहुत से तरीके हैं जिन से मुनाफा होता है। जैसा मैं ने आप से कहा जो बारह टाप बैंक्स

थे उनका जो मुनाफा था वह ७.३५ करोड़ रुपये था, एक साल का ५० परसेंट टैक्स देने के बाद और अपना रिजर्व फंड अलग रखने के बाद उनका इतना मुनाफा था। इसी तरह से दूसरे बैंक्स भी थे।

अब थोड़े से शब्दों में मैं यह कहना चाहती हूं कि एक जगह यहां किसी डिबेट में मंत्री महोदय ने बतलाया कि बैंक्स न लेने का कारण यह है कि प्रइम मिनिस्टर ने यह कहा है, उन को यहां पर कोट किया गया कि हम चाहते हैं कि हम बैंकों को न लें क्योंकि वह प्राइवेट हाथों में रहेंगे तो उनका एक्स्पैन्शन होगा। गांव गांव में बैंक खुलें यह हम चाहते हैं। तो मैं इस को .....

Shri B. R. Bhagat: Who said it?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : एक दिन डिबेट में कहा गया था कि इस तरह से उनका एक्सपैनशन होता है। मेरा आप से कहना है कि अगर आप देखें तो पायेंगे कि इस वक्त हमारे यहां ५१११ ब्रांचिज हैं। लेकिन यह जो ५,१११ ब्रांचिज हैं वे देहातों में हिन्दुस्तान के नहीं हैं। उनमें से १७१२ सेंटर में हैं। गांवों में केवल ६५७ ब्रांचिज हैं। १७१२ सेंटर्स में से २२६ जगहों पर प्राइवेट बैंकों की ब्रांचिज नहीं हैं। वे स्टेट बैंक की ब्रांचिज हैं। इस के ख़िलाफ़ आप देखेंगे कि स्टेट बैंक को जून, १९५५ में ले लिया गया। सन् १९५५ के एन्ड तक स्टेट बैंक की कुछ ४८४ ब्रांचिज थीं और सन् १९६१ के एन्ड तक उसी स्टेट बैंक की ब्रांचिज ६४६ के करीब हो गईं, और इस वक्त तक तो ऐसा मालूम होता है कि उस की ब्रांचिज १,००० से ऊपर हो गई हैं। इस लिए मैं कहना चाहती हूं कि बैंक्स के एक्स्पैन्शन का जहां तक सवाल है वह बग़ैर नैशनलाइज़ेशन के नहीं हो सकता है।

मुझ को उम्मीद है कि जो कारण मैं ने दिये हैं उन से मैं ने मंत्री महोदय को कन्विंस कर लिया होगा कि बैंकों को ले लेना चाहिये। अगर सरकार यह कहना चाहती है कि पैसा कहां से आयेगा बैंक्स को नैशनालाइज़ करने के लिये कम्पेन्सेशन का पैसा कहां से आयेगा तो मैं बतलाना चाहती हूं कि यह एक एसी इंडस्ट्री है जिस में कम से कम कैपिटल लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा परसेन्टेज मुनाफे का होता है। सरकार को सब से कम रुपया चाहिये बैंक्स को लेने के लिए और उन को टेक ओवर कर के स्टेट के बड़े भारी रिसोर्सेस हो सकते हैं। जैसा मैं ने बतलाया कई बैंकों का जो पेड अप कैपिटल है वह सिर्फ़ ३० करोड़ रुपये के करीब है। शायद २९.२१ करोड़ रुपये है। लेकिन उन शेयरों की प्रेज़ेन्ट मार्केट वैल्यू जो है वह ६१.२ करोड़ रूपये के करीब है। उस में से भी १३ से १५ परसेन्ट शेअर एल० आई० सी० उन बैंकों में रखता है। अगर गवर्नमेंट पूरे बैंक को टेक ओवर न करे, सिर्फ़ ५१ परसेन्ट शेअर्स उन बैंकों में कर ले, बाक़ी उन्हीं के पास ही रहने दे तो भी कम से कम कंट्रोल तो सरकार का हो ही जायेगा। मैं ने प्राइम मिनिस्टर का एक लेख पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण न भी करें, तो भी उस पर पूरा कंट्रोल करने का मतलब वही हो जाता है। मतलब यह हो जाता है कि अगर ५१ परसेन्ट शेअर एल० आई० सी० ले ले और बाक़ी उन के ही पास रहने दे तो सिर्फ़ २२ करोड़ रुपया एक बार लगा देने से ही इतने भारी रिसोर्सेज और ३५ करोड़ मुनाफा रुपया प्रति वर्ष के उस के पास आ जायेंगे। एक दफा २२ करोड़ रुपया देने के बाद सारी ताकत प्राफ़िट की और डिस्पोजल की, क़र्ज़ देने की और प्लैन को इम्प्लिमेंट करने की, स्टेट के हाथ में आ जायेगी। मेरे आर्गूमेंट के लिए इतना कह देना ही काफी है। इस लिए मैं कहना चाहती हूं कि इस मौजूदा इमर्जेन्सी में सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर के जल्दी से जल्दी स्टेट उस के रिसोर्सेज को अपने हाथ में ले ले।

Mr. Deputy-Speaker: Resolution moved.

[Mr. Deputy-Speaker]

"In view of the emergency created by the Chinese aggression, this House is of opinion that banks should be nationalised in order to mobilise the national resources."

Shri Prabhat Kar. Hon. Members will take five to six minutes each. There are about ten Members to speak.

Shri Prabhat Kar (Hooghly): I may be given at least ten minutes.

Mr. Deputy-Speaker: I have to give chance to some more Members also.

Shri Prabhat Kar: On behalf of the All India Bank Employees' Association, we have been demanding for the last five or six years for the nationalisation of banks. I am thankful to the hon. Member for having brought forward this resolution, and she has explained in very great detail how it would benefit the country, and the State and the people if the banks are nationalised.

I would only point out that recently we had the report of the Vivian Bose Commission. If we go through the pages of that report, we find that in every transaction, one or the other bank is involved. That means that all the fraudulent transactions which have been brought to our notice in the Vivian Bose Commission's report were done with the connivance of the banks that were at the control of the Dalmia-Jain group. We have heard earlier of the Mundhra deals in relation to the LIC. I would only ask this House to remember one thing. Who made Mundhra what he is today? How could he purchase the Jesp company's shares by the fraudulent transaction of foreign exchange purchasing from the London market? Who helped him? Which bank helped him? Which bank helped Mundhra in supplying the foreign exchange? That was again a banking company. I do not want to mention the name, but I would say that this was done with the connivance of one of the foreign exchange banks.

Today, as the hon. Member has rightly pointed out, when we are in need of mobilisation of all resources, it is essential that if we want to gear up our economy for our defence and development, the banks should be nationalised. The role of bankers in our country's economy has already been pointed out. I know that the Deputy Minister of Finance will say that Government are having control over the banks through the Reserve Bank of India, and in every affair of banking, the Reserve Bank makes an inspection and controls them.

I would only draw his attention to the *Trend and Progress of Banking in India* brought out in 1961; the one for the year 1962 which is the latest has not yet been published. At page 109 that publication gives the progress made by the banks in the rectification of the defects pointed out to them. Item 13 relates to 'Concentration of advances in the hands of a few borrowers'. The defects were pointed out to them. And what was the result? The result was that it increased by 'plus 47.7 per cent'. This is the result of the Reserve Bank's control. Item 14 relates to large advances to the directors, their relations, and associates and concerns in which everyone of them is interested. The defects were pointed out to them. And what was the result? It increased by plus 42·8 per cent. This is the result of the control of the Reserve Bank of India, in regard to two major points, concentration, and large advance to the board of directors in firms where they are interested. These have gone on increasing by 47 7 and 42.8 per cent respectively. After this, if it is said that the Reserve Bank can still control them, I would say that this type of control will not do and it is necessary that the banks should be nationalised.

Look at the development of the State Bank of India. We have been talking today about rural banking. It is a tragedy that in such a big country like India we have got only 1712 branches

of this Bank. Most of these branches are in big cities. So 90 per cent of the country is deprived of banking facilities. What do we find? 8 public sector banks have got more than 1500 branches while 295 private sector banks have got 3611 branches. This is the result. This is the difference between the public sector and the private sector. Already, as a result of the nationalisation of the Imperial Bank of India and its subsidiaries, we have seen this difference. It is essential, if we are serious about gearing up our economy, if the hon. Minister is serious about putting so many tax burdens on the common people in order to build up our economy and have development and also have defence, that the first step we should take should be to take over the banking industry.

It is not possible to list here all the malpractices of the banks, even in spite of regulation by the Reserve Bank. The Palai Central Bank has gone into liquidation. I am prepared to tell the Finance Minister—we have done it on many occasions what are the types of manipulations indulged in by these banks. But no steps have been taken. Recently, they have decided to inquire into some Dalmia-Jain concerns. But what is true of this group is true of each and every one of the others. I am prepared to take the risk of giving names and also challenging in the case of each and every bank as to what type of manipulations have been going on, as they have been going on in the case of the Dalmia-Jain group. In each and every case, we find that the big boses are linked with this type of thing. But no inquiry is being made.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Why does he not give particulars of those manipulations?

Shri Prabhat Kar: If I mention the names, immediately there would be a run in the banks concerned. That is why I do not want to do it. But I want Government to look into the matter. This matter cannot be dealt with unless the banks are taken full control of by Government.

Dr. M. S. Aney: Is that the case with each and every bank?

Shri Prabhat Kar: It is essential to take over the banks. In doing so, the money that will be spent will be the very minimum. The share capital of the banking industry constitutes 1.9 per cent of the total working capital of the companies and the profit in this industry is cent per cent. That is why a special representation has been made to the Finance Minister not to make SPT applicable to this industry, because the share capital is so disproportionate that it cannot be put on par with other industries.

If this is the position, naturally the shareholders or the directors will tend to be irresponsible, and they are irresponsible. That is why there is no development taking place in commerce and industry. We have already pointed out how under-invoicing of exports and over-invoicing of imports is resorted to and how it is done. It is done with the connivance of the banking industry. Here we come before the House and ask for the imposition of taxes, but we do not take the steps which will stabilise our economy, namely, nationalisation of the banking industry.

I therefore request that at least now, at this particular moment, when we are passing through an emergency, when it is essential that we should mobilise our resources, when all efforts are being made, when even the compulsory deposit scheme is applied to the low income group, it is high time we nationalised the banking industry. That will gear up the economy, that will help development of the country, that will bring us resources and that will also check malpractices which prevail today in commerce and industry.

Shri Thirumala Rao (Kakinada): Can I ask the hon. Member if cooperative banks also should be nationlised completely by Government?

Shri Prabhat Kar: I have spoken about commercial banks, not co-operative banks.

Shri P. R. Patel (Patan): The question for the consideration of the House and the country would be this, whether nationalising the banks under the present circumstances would be serving the country or would be a disservice to the country.

I may tell you I do not hold any share in any banking corporation, and my deposit with some bank may be much less than what I nave in the State Bank of India branch in Parliament House. This is sufficiet to show that perhaps my deposit would be much less than the deposits of my lady friend.

But I do not support her. The reason is this. The argument put forward is that the banks are making very big profits and that if they are nationalised, the profits can be utilised by the Government for the country. It is a very good argument. She says that they are paying less interest to the depositors and charging more interest for loans that they give to others. What is the difference, does she know? For fixed deposit today the rate of interest is 5 per cent, even 5½ per cent, and the loan interest would be about 9 per cent. Is there no risk in accepting deposits and giving loans out of them? If that is a profitable business, I would request my communist friends and the lady friend to do the business, because, after all, it does not require any investment or anything.

Shri Prabhat Kar: Still, hundreds of people are flourishing in that business.

Shri P. R. Patel: It is simple: get the deposits and charge more interest on the loans. But that is not the question. Much depends on the credit, integrity and efficient working of the persons at the top including the managers, directors and the chairman too. Apart from that, there is the credit of the bank. People feel putting money in the particular bank is always safe.

Shri Prabhat Kar: That is why the deposit insurance scheme has been introduced.

Shri P. R. Patel: That confidence comes not by attacking the private sector or only by speaking of the public sector. That confidence comes by working for years and years.

She said this bank is of a particular group, this is Birlas' Bank, this is Dalmias', this is Walchand's Bank, this is Mafatlal's Bank. Well, they do not own those banks. She must know that after all the bank is owned by the shareholders.

Shri D. C. Sharma: In name only.

Shrimati Subhadra Joshi: I said that.

Shri P. R. Patel: In the public sector too, whether it is in China or Russia, when we say that people own the whole concern, what is "people"? Today People's Government is there everywhere, but who rules, whose voice prevails? After all, it is the Cabinet that rules on behalf of the whole country. They say: you are our masters, we are your servants. These are very good slogans but whether it is the private sector or the public seetor, it is the few persons at the top, call them directors or managers, who rule. There is one thing more. Control in the private sector of the share holders is much more than the control of Parliament over the public sector.

Shri D. C. Sharma: No, no.

Shri P. R. Patel: Prof. Sharma has never been in business: he is a professor; he gives good speeches.. *(Interruptions)*.

Shri D. C. Sharma: He is right; I have never done any business.

Shri P. R. Patel: In the company meetings of private sector concerns, some shareholders put so many odd questions and get information and put the directors also in very embarrassing position. Our public sector is there.. (*Interruptions.*) I do not want to criticise it; I am not against the public sector. I am not absolutely in favour of the private sector. I am in favour of good banking system and industry in the country. It may be in the public sector it may be in the private sector.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri P. R. Patel: Sir, I request you to give me a few more minutes. I was disturbed by this lady.

Mr. Deputy-Speaker: I have no time to give you. You should wind up now.

Shri P. R. Patel: There is one thing more. It is said that they give loans to a very few. I do not know these things. But if there is a big factory worth about Rs. 15 crores and a bank gives Rs. 1 crore to such a few persons, they make more crores instead of distributing the money here and there. The question is: have these loans contributed to the development of the industry in the country? That is the point.

A minute more, and I shall have concluded. We have also got banks: the State Bank, for instance. We can have our branches in each and every village. Who comes in the way? It is not simply possible. The economic side has also to be considered. We cannot have a branch in each and every village. We have got our post offices also. Is it not the public sector? There is the saving system deposit system and all these things. So, that question is not important. We have spread our postal system in all the villages. So, the question does not arise. I do not want to take more time. Thank you for the time given.

Shri D. C. Sharma: I want to ask him one question: who gets the profits in the public sector? Who, in the private sector?

Mr. Deputy-Speaker: Shri Deo.

Shri P. K. Deo: Mr. Deputy Speaker, Sir, if you go through the Resolution you will see that the wording is as follows:

> "In view of the emergency created by the Chinese aggression, this House is of opinion that banks should be nationalised in order to mobilise the national resources."

I cannot appreciate if there is any sincerity behind this Resolution and why the lady Member should have taken this opportunity of emergency to preach socialism. She should not have taken shelter behind the mantle of emergency. When the fundamental rights of the citizens are abrogated, when any action of the Government cannot be justiciable in a court of law, a proposal like this seems ridiculous. This emergency is of a temporary nature, and if we take the plea of emergency and start doing such a thing, it will have a far-reaching effect in the economy of this country.

Nationalisation is meaningless if it is not properly manned by persons inspired by missionary spirit or if the administration is not impersonal and incorruptible and if there would be encroachment on the freedom of the individual or in his pursuit of his legitimate professions. After all, human beings are not to be reduced as pigs in the stable of socialism. It is meaningless so long as the gentlemean opposite are in the helm of affairs.

[Shri P. K. Deo]

Let us examine the performance of our nationalised industries. All cannons of ethics and administrative morality are thrown to the winds and the beneficiaries of the nationalisation are only the partymen. While the tax-payers' money is wasted in providing jobs to the favourites and to the defeated party candidates in the elections, still, this thing has been going on. I do not like to name the various candidates who have been defeated and who have been employed in the nationalised undertakings because that will be tabooed by you. I have a long list of 12 to 15 persons. Even though the Estimates Committee was time and again saying that recruitment to....

The Minister of Mines and Fuel (Shri K. D. Malaviya): Is a person supposed to be disqualified for it if incidentally he loses in the elections? How does the hon. Member say that if a person loses in the elections, he is disqualified for other things? (*Interruptions*).

Shri P. K. Deo: I would like the hon. Minister to name one person who has been defeated in the elections, belonging to the opposite party and who has been provided with a job by the Government....

Shri K. D. Malaviya: What is the disqualification about it?

Shri P. K. Deo: It is favouritism. It is nothing but favouritism; time and again, it has been pointed by the Estimates Committee, not only of this third Lok Sabha but of the second Lok Sabha and the first Lok Sabha that recruitment to the public sector undertakings should be done by a special Public Service Commission. In para 75 of their 39th Report (1st Lok Sabha), the Estimates Committee observed that recruitment of officers in public undertakings should be made by a separate Public Service Commission....

Shri Reddiar (Tindivanam): What is the use of quoting what happened before?

Shri P. K. Deo: If it is a point of order, I shall yield. Otherwise not.

Shri Reddiar: What happened some years ago need not be referred to now. Would he limit his speech to the present state of affairs?

Mr. Deputy-Speaker: He is reading from the Estimates Committee's report.

Shri Reddiar: He is referring to something which has happened sometime back.

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): On a point of order. He said something about pig in the stable or something.

Shri P. K. Deo: She cannot raise a point of order on something, if the lady Member does not know herself.

Mr. Deputy-Speaker: He is reading from the Estimates Committee's report. Please sit down.

Shrimati Lakshmikanthamma: The point of order is that he said something against socialism. It has been laid down in the Constitution that we believe in economic equality, social equality and so on. How can he talk against it?

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of order. That is his view.

Shri P. K. Deo: The recommendation that recruitment to the public undertakings should be made through a separate Public Service Commission was first made by the Estimates Committee of the first Lok Sabha, in its 39th report. It was again reiterated in its 38th report of the second Lok Sabha, and again, while dealing with the National Coal Development Corporation, this recommendation was reiterated by the Estimates Committee in its 32nd report of Third Lok Sabha.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): On a point of order. What we are now discussing is a simple resolution about the nationalisation of banking. The hon. Member is taking this opportunity to damn the public sector projects. It should not be done.

Mr. Deputy-Speaker: That is what I am telling him.

Shri S. M. Banerjee: He should come to the point.

Shri P. K. Deo: I am coming to the point, although what I have spoken is not irrelevant.

Mr. Deputy-Speaker: He can continue his speech next time.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 15, 1963/Chaitra 25, 1885 (Saka).